दैनिक
स्वर्णिम प्रदेश
PRN: MCN/329/2025-2027
epaper.swarnimpradesh.in
संरक्षक: मां वैष्णो देवी

विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें
अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो दैनिक स्वर्णिम प्रदेश आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन की बधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनी नोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।
ईमेल: swarnimpradesh@yahoo.com
या वाट्सऐप नं. 8898271111

वर्ष : 8 • अंक : 299 • मुंबई, शनिवार 16 मई, 2026 • पृष्ठ : 6 • मूल्य: 2 रुपये • संपादक : सुनील कुमार तिवारी • Email: swarnimpradesh@yahoo.com www.swarnimpradesh.in

पीएम मोदी ने की यूएई पर हमलों की निंदा, स्वतंत्र होर्मुज के लिए कूटनीति पर जोर

संवाददाता

अबूधाबी/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) यात्रा के दौरान कई अहम समझौते और निवेश घोषणाएं की गई। दोनों देशों के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर समझौता हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आपूर्ति से जुड़े समझौतों पर सहमति बनी।

गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा भारतीय अवसंरचना क्षेत्र, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छह दिवसीय विदेश प्रवास के दौरान भारतीय समयानुसार शुक्रवार सुबह अबूधाबी पहुंचे। यह उनकी पांच देशों की यात्रा की शुरुआत है। वे आगे नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जायेंगे। अबूधाबी हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। आगमन के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की संक्षिप्त यात्रा के दौरान आज यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की उपस्थिति में भारत और यूएई ने समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार दोनों नेताओं ने व्यापक मुद्दों पर सार्थक बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को अधिक मज़बूत करने पर चर्चा की। चर्चा का मुख्य केंद्र ऊर्जा, व्यापार और निवेश, ब्लू इकोनॉमी, फिनटेक सहित प्रौद्योगिकी, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्र रहे। उन्होंने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, रक्षा, शिपिंग सहित बुनियादी ढांचे और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों का आदान-प्रदान भी हुआ - जिससे भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गति मिली। यूएई ने भारत में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की भी घोषणा की। इससे हमारे बाज़ार और बुनियादी ढांचा और अधिक मज़बूत होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, "यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।" प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए यूएई के राष्ट्रपति की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया। उन्होंने कठिन समय में यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को दी गई देखभाल के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।

7 विषयों पर सहमति, 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान 7 अहम विषयों पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर समझौता हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आपूर्ति से जुड़े समझौतों पर सहमति बनी। गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा भारतीय अवसंरचना क्षेत्र, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तथा अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े समझौते का उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। इससे भारत को कच्चे तेल और एलपीजी की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह समझौता भविष्य में वैश्विक संकट या तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान भारत को राहत देने में मदद करेगा। एलपीजी आपूर्ति सहयोग समझौते के तहत यूएई भारत को दीर्घकालिक आधार पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस उपलब्ध कराएगा। इससे भारत की घरेलू गैस जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के साथ दोनों देशों की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगा।

मप्र हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: धार की ऐतिहासिक भोजशाला को माना मंदिर

■ मुस्लिमों को नमाज के अधिकार का एएसआई के आदेश को किया खारिज

संवाददाता

इंदौर। मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। उच्च न्यायालय ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि भोजशाला परिसर मंदिर ही है। मस्जिद पक्ष को अलग जमीन दी जाएगी। इसके लिए मस्जिद पक्ष सरकार से याचिका करे। मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार और एएसआई यह फैसला लें कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा।

1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा। पीठ ने कहा कि ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। न्यायालय ने एएसआई का 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। न्यायालय ने इस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। न्यायालय ने कहा है कि मस्जिद पक्ष यदि सरकार को आवेदन देता है तो उसे अलग जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही यह कहा कि सरकार इंग्लैंड से वाग्देवी की प्रतिमा लाने का प्रयास करे। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भोजशाला मामले में मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगलपीठ में छह अप्रैल से 12 मई 2026 तक नियमित सुनवाई हुई। इन 24 दिनों में कुल 43 घंटे चली सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपने-अपने तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके बाद 12 मई को न्यायालय ने सभी याचिकाओं में निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। इस दौरान अंतरसिंह की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि दोनों पक्षों में सौहार्द बना रहे, इस तरह की व्यवस्था का आदेश दिया जाए। उच्चतम न्यायालय जाएगा मुस्लिम पक्ष भोजशाला के फैसले पर धार शहर काजी वकार सादिक ने कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान है। उनकी ओर से सलमान खुर्शीद और शोभा मेनन ने तथ्य रखे थे। हम फैसले की समीक्षा करेंगे। इसके बाद हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे। फिलहाल, भोजशाला के मेन गेट पर बैरिकेड्स लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। इसके बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। भोजशाला मामले के फैसले के मद्देनजर इंदौर और धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। शुक्रवार होने से संवेदनशीलता और बढ़ गई है, क्योंकि इसी दिन मुस्लिम समाज भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज अदा करता है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने और अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है।

सड़क पर जुमे की नमाज को लेकर हंगामा, पुलिस ने खाली करवाई सड़क

संवाददाता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के राजा बाजार इलाके में शुक्रवार को सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस द्वारा सड़क खाली कराने की कोशिश के दौरान नमाजियों और पुलिसकर्मियों के बीच बहस और नारेबाजी हुई। बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इलाके को खाली कराया गया और यातायात सामान्य किया गया। जानकारी के अनुसार, राजा बाजार इलाके में वर्षों से सड़क पर जुमे की नमाज अदा की जाती रही है। हालांकि, राज्य की नई सरकार द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश के बाद शुक्रवार को पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से सड़क खाली करने को कहा। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस से धक्का-मुक्की करने की कोशिश की। इसके साथ ही नारे - तकबीर व अल्लाह - हू - अकबर के नारे लगाए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को तैनात किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक, कोलकाता के अधिकांश इलाकों में मस्जिदों के भीतर शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की गई और केवल राजा बाजार इलाके में विवाद की स्थिति बनी। बाद में पुलिस ने सड़क खाली कराकर यातायात सुचारु करा दिया।

खार पूर्व में सोलंकी मेडिकल स्टोर कर रहा ओवरचार्ज, बिल देने से किया मना

एफडीए और वैध मापन विभाग से कार्रवाई की मांग

संवाददाता

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफडीए) में अधिकारियों की कमी का फायदा कई मेडिकल स्टोर संचालक खुलेआम उठा रहे हैं। दवाओं और खाद्य पदार्थों की बिक्री में मनमानी किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला खार पूर्व स्थित जवाहर नगर इलाके के सोलंकी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का है, जहां ग्राहकों से तय मूल्य से अधिक राशि वसूले जाने और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री किए जाने की बात सामने आई है।

जिसकी सत्यता भी सामने आई जब शुक्रवार शाम संवाददाता द्वारा मेडिकल स्टोर से 250 एमएल की दो एनर्जी ड्रिंक "हेल" खरीदी गईं। एक बोतल की कीमत 60 रुपये होने के हिसाब से कुल राशि 120 रुपये बनती थी, लेकिन दुकानदार द्वारा 130 रुपये वसूले गए। बिल मांगने पर दुकानदार ने आनाकानी की और कथित तौर पर कहा, "लेना है तो लो, नहीं तो वापस कर दो।"

इतना ही नहीं, मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री भी लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की मनमानी से ग्राहकों का आर्थिक शोषण हो रहा है और दवाओं की अनियमित बिक्री जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। अब देखना यह है कि वैध मापन शास्त्र विभाग और एफडीए ऐसे मेडिकल स्टोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब करते हैं, जो तय मूल्य से अधिक वसूली करने और बिना चिकित्सकीय पर्चे दवाओं की बिक्री जैसे नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं।

भोजशाला के मंदिर करार देने के हाई कोर्ट के फैसले का विहिप ने किया स्वागत

संवाददाता

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मध्य प्रदेश के धार शहर स्थित भोजशाला को मंदिर करार दिए जाने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे अविलंब हिंदुओं को सौंपने की मांग की है।

विहिप के संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन ने उच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह हिंदू समाज के 550 सालों के संघर्ष का फल है। सभी इतिहास से भलीभांति परिचित हैं। बावजूद इसके मुस्लिम समाज सच्चाई को झुठलाता रहा है। इतिहास गवाह है कि हमारे सैंकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। विहिप किसी भी समाज का विरोधी नहीं है लेकिन हिंदू समाज की आस्था को देखते हुए सभी समाज को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोजशाला के बाद अब मथुरा और काशी के मंदिर के मामले में भी हिंदू समाज की जीत होगी। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार से भोजशाला को अविलंब हिंदुओं को सौंपने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से भारत में चुराई गई मां सरस्वती की प्रतिमा को ब्रिटेन से वापस लाने की भी मांग की। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि भोजशाला में हिंदू पूजा-अर्चना की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई है। ऐतिहासिक साहित्य और रिकॉर्ड यह साबित करते हैं कि विवादित क्षेत्र भोजशाला था, जो परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की अधिसूचनाओं और सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया। एएसआई के पुरातात्विक साक्ष्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया गया है।

युद्ध का मैदान बदल रहा इसलिए आने वाली जंगें हवा में हुआ करेंगी : एयर चीफ

संवाददाता

नई दिल्ली। युद्ध का मैदान बदल रहा है इसलिए आने वाली जंगें हवा में हुआ करेंगी। यही वजह रही कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में पहली बार भारत-पाक संघर्ष के दौरान ड्रोन सबसे पसंदीदा हथियार बने। ड्रोन आने वाले रोबोटिक युद्ध का सिर्फ शुरुआती एक्शन हैं। आने वाले समय में तीनों सेनाएं एक ही एयर में ऑपरेट करेंगी। इसके लिए अंतरिक्ष में भी आपसी तालमेल होना चाहिए। हवा में युद्ध करने से ऑपरेशन के दौरान इंसानों की जान का खतरा कम होता है और कम कीमत ही युद्ध लड़ा जा सकता है। इस तरह के विचार नई दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में एक एयरोस्पेस पावर सेमिनार में शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने रखे हैं। स्वायत्त रक्षा थिंक टैंक सेंटर फॉर एयरपावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सहयोग से यह संयुक्त गोष्ठी आयोजित की गई। इस सेमिनार में वरिष्ठ सैन्य हस्तियों, क्षेत्र के विशेषज्ञों और विशिष्ट प्रतिभागियों को एयरोस्पेस क्षमता बढ़ाने में रखरखाव दक्षता और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाया गया। इस सेमिनार में भारत की वायु सेना को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतिगत रूपरेखाओं पर केंद्रित पैनल चर्चाएं हुईं। विशेषज्ञों ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रव्यापी विजन के अनुरूप रखरखाव रणनीतियों को अपनाने पर अपने विचार साझा किए। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि 'ड्रोन और अनमैन्ड एरियल (यूए) सिस्टम का यह विषय बहुत प्रासंगिक है, यह एक सच्चाई है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़ाई का मैदान बदल गया है। हम केंद्रित वायु शक्ति से विकेंद्रीकृत तक और स्वायत्त तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि यूए सिस्टम हवाई शक्ति का ही विस्तार हैं। इस तरह के ऑपरेशन के दौरान इंसानी जान का खतरा भी कम होता है। जैसा कि मैंने कहा कि यह एयर पावर का ही एक्सटेंशन है, इसलिए जब आप यूए सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, तो एयर पावर के सभी नियम लागू होंगे।

आरजी कर कांड और भ्रष्टाचार पर शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, तीन आईपीएस समेत कई अधिकारी सस्पेंड

संवाददाता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था, जेलों में कथित भ्रष्टाचार और आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया। नवान्न में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान प्रशासन के कई स्तरों पर "रक्षक ही भक्षक" जैसी स्थिति बन गई थी और अपराधियों के साथ प्रशासन के कुछ लोगों की सांठगांठ विकसित हो गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इस पूरे तंत्र को तोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम में कैदियों के पास बड़ी संख्या में स्मार्टफोन इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें मिली थीं। इस शिकायत के बाद डीजी करेक्शनल होम एन. रमेश बाबू को मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। डीजी कारा एन. रमेश बाबू ने बताया कि कोलकाता पुलिस की मदद से प्रेसिडेंसी जेल में अचानक छापेमारी की गई। 10 विशेष टीमों ने करीब चार घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जेल के अलग अलग गुप्त स्थानों से कुल 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अब इस बात की जांच की जा रही है कि ये मोबाइल फोन जेल के भीतर कैसे पहुंचे, कौन उनका इस्तेमाल कर रहा था और किन लोगों से संपर्क बनाए रखा जा रहा था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंपी जाएगी। साथ ही प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम के सुपरिंटेंडेंट एन. कुजूर और चीफ कंट्रोलर दीप्त घोड़ाई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले का भी उल्लेख किया।

संपादकीय

युद्ध संकट हमारी दहलीज पर

प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काफिला कम कर उदाहरण पेश किया है। बुधवार को दो वीडियो सामने आए। एक में काफिले में मात्र दो कारें थीं और दूसरे वीडियो में 4 कारें दिखाई दीं। यह किफायत नहीं, जोखिम है। प्रधानमंत्री से ऐसी कोई अपेक्षा और शिकायत नहीं थी। प्रधानमंत्री एसपीजी के सुरक्षा-कवच में रहते हैं। उस सुरक्षा का अपना प्रोटोकॉल होता है, लिहाजा काफिले में 15 या 20 कारें हैं, इस पर सवाल उठाना ही बेमानी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की नजीर का अनुसरण रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सडक़ परिवहन मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने किया है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और बिहार के 'भगवा मुख्यमंत्री' सम्राट चौधरी अब भी 19-20 कारों के काफिले के साथ घूमते नजर आए हैं। बहरहाल उन्हें भी जल्द ही सद्बुद्धि आ जाएगी। काफिलों की किफायत और अन्य व्यवस्थाएं स्थायी होनी चाहिए, भेड़चाल या ढोंग के मायने बेहद खतरनाक होंगे। बचत प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि तक ही अपरिहार्य नहीं होनी चाहिए। सरकारों में सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक स्तर के आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को अलग-अलग सरकारी वाहन दिए गए हैं। कटौती उनमें बहुत जरूरी है। वे सभी 2-4 किमी दूर के सरकारी आवासों से दफ्तर तक आते हैं और फिर घर लौटते हैं। सरकारी वाहनों की ऐयाशी और भौकाल खत्म किए जाने चाहिए। ऐसे अधिकारियों को एक विशेष बसनुमा वाहन से दफ्तर लाया जाए और शाम को घर छोड़ा जाए। यह संवैधानिक प्रोटोकॉल नहीं है कि सभी अफसर 'महाराज' की तरह सुविधाएं भोगें। यदि देश में पेट्रोल-डीजल का संकट है, तो किफायत अपरिहार्य है। आपातस्थिति के लिए तो छूट हमेशा बनी रही है। दरअसल ये अधिकारी ही हमारी व्यवस्था के नीति-निर्माता हैं, लिहाजा निरंकुश-से हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन बैठकों की अपील की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह कुछ मुख्यमंत्रियों ने इस व्यवस्था को लागू करने के आदेश भी जारी करवा दिए हैं, तो ये आला अफसर भी अमल करें। यदि प्रधानमंत्री की पूरी अपील को स्वीकार कर लागू किया जाए, तो साल भर में 11.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। यह बहुत बड़ी राशि है। यदि काफिला छोटा कर तेल बचाया जाता रहा, तो साल भर में करीब 91,250 लीटर डीजल बचेगा। इस तरह 1 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी। यह शोशेबाजी, रुतबेबाजी अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ईरान युद्ध से उपजे संकट भारत की दहलीज तक आ गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक सार्वजनिक मंच से कहा है कि यदि ईरान युद्ध जारी रहा और लंबा खिंचा, तो सरकार को पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम बढ़ाने पड़ेंगे। रसोई गैस का सिलेंडर भी महंगा होगा, क्योंकि ये सभी आयातित हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी बड़े दुखी अंदाज में खुलासा कर रहे हैं कि देश की तेल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए हररोज का औसतन घाटा झेलना पड़ रहा है। युद्ध के 75 दिनों में यह घाटा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। निश्चित है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। बुधवार को कच्चे तेल के दाम 108 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। हालांकि युद्ध के इस अंतराल में 98 देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 40 देशों को तेल से जुड़े प्रोटोकॉल लागू करने पड़े हैं। अमरीका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस समेत वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों को पेट्रो उत्पादों की राशनिंग करनी पड़ी है और कई प्रोटोकॉल लागू करने पड़े हैं। भारत ने इन 75 दिनों में यह बोझ अपनी जनता पर पडऩे नहीं दिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब संकट बढ़ता जा रहा है, तो शुरुआत बचत से की जा रही है। बचत के ऐसे आह्वान लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, डा. मनमोहन सिंह सरीखे प्रधानमंत्रियों ने भी किए थे। अब आईएमएफ के मानकों के मुताबिक, भारत अभी गंभीर संकट में नहीं है, करीब 11 माह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा पर्याप्त है, लेकिन डॉलर की तुलना में 'रुपया' 96 के करीब पहुंच चुका है, आयात के लिए 34,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ा है, लिहाजा सावधान होना तो जरूरी है। यह बात भी सामने आ रही है कि पेट्रोल-डीजल, सोना तथा अन्य सामान, खाद्य पदार्थ भी महंगे होने लगे हैं। सरकार को कोशिश यह करनी है कि जरूरी चीजें महंगी न हों।

डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 'रुपए' में 95.28 तक की ऐतिहासिक गिरावट ने संकट को गहरा दिया है। इस समय 'रुपया' दुनिया की दूसरी सबसे कमजोर मुद्रा है, जिसमें 12 फीसदी अवमूल्यन हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है, लेकिन भारत सरकार ने विदेशों से 168 टन सोना खरीदा है। अब भारत के पास सोने का कुल भंडार 880 टन का है। इसे 'राष्ट्रीय सुरक्षा' से जोड़ कर आंका जा रहा है। दरअसल हमारा बुनियादी सवाल सरकारी व्यवस्था और नेताओं की जमात से है। देश में प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और आम अति विशिष्ट चेहरे भी लंबे-चौड़े काफिलों के साथ चलते हैं। यदि वाकई संकट के हालात हैं, तो मुख्यमंत्री और मंत्री सरकारी हेलीकॉप्टर पर सवार क्यों रहते हैं? क्या हवाई उड़ानें 'पानी' से चलती हैं? हमारे जन-प्रतिनिधि रेलगाड़ी के विशेष कक्ष में सफर क्यों नहीं कर सकते? यदि सार्वजनिक परिवहन नेताओं के लिए 'असुरक्षित' हैं, तो रेलवे में असंख्य यात्रियों की सुरक्षा दांव पर क्यों लगा रखी है? हम प्रधानमंत्री को अपवाद के तौर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह देशहित में, देश के लिए ही, सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी के तौर पर 'विशेष वाहन' का इस्तेमाल करते हैं और अब मई में ही 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे, लेकिन हम प्रधानमंत्री के 'रोड शो' पर सवाल और आपत्ति जरूर करेंगे। हमारा राजनीतिक नेतृत्व पहल करे, बचत के नए आयाम स्थापित करे, आम जन-प्रतिनिधि बने, तो यह देश भी उसका अनुसरण करेगा। दरअसल युद्ध और होर्मुज जलमार्ग बंद होने के कारण ऊर्जा-संकट दुनिया भर में है। कच्चा तेल महंगा मिलने के कारण भारत को हररोज 1619 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। आयात बिल में खाद्य तेल पर 1.86 लाख करोड़ और खाद पर 1.38 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बाजार में यूरिया, डीएपी की कीमतें दोगुनी बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा, सरकार को खाद पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की सबसिडी किसानों को देनी पड़ रही है। नतीजतन बुनियादी ढांचे और विकास पर किया जाने वाला पूंजीगत खर्च कम करना पड़ रहा है। चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। तमाम आयातों पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है। यह 'अकाल' हम 1990-92 के दौर में झेल चुके हैं, जब देश का 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था।

विरोधियों को छोड़कर सबके लिए खुला है होर्मुज मार्ग: ईरानी विदेश मंत्री

संवाददाता

नई दिल्ली। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को कहा कि ईरान भी होर्मुज जलडमरुमध्य को पूरी तरह सुरक्षित और खुला रखना चाहता है। युद्धरत देशों के जहाजों को छोड़कर अधिकांश जहाजों के लिए यह मार्ग खुला भी है। हालांकि परिस्थितियों के कारण ईरानी सेना के साथ समन्वय जरूरी है। भारत के कई जहाजों को भी ईरान ने सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए नई दिल्ली आए ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने शुक्रवार को यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।

उन्होंने कहा, "हॉर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में हमारी भी यही इच्छा है कि इसे पूरी तरह से फिर से खोल दिया जाए। जहाँ तक हमारा सवाल है, हॉर्मुज जलडमरूमध्य खुला हुआ है या नहीं। सभी जहाज़ वहाँ से गुज़र सकते हैं- सिवाय उन देशों के जहाज़ों के जो हमारे साथ युद्ध की स्थिति में हैं और हमारे विरुद्ध लड़ रहे हैं। जो जहाज़ वहाँ से गुजरना चाहते हैं, उन्हें जाहिर तौर पर हमारी सेना के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए क्योंकि वहाँ कुछ बाधाएँ मौजूद हैं। ऐसे में हम उन्हें सुरक्षित मार्ग दिखाएँगे, जैसा कि हमने कई भारतीय जहाज़ों के साथ किया है।" ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि फिलहाल संघर्ष विराम लागू है, हालांकि स्थिति नाजुक बनी हुई है। उनका कहना था कि ईरान किसी भी दबाव या सैन्य कार्रवाई के आगे नहीं झुकेगा। समस्या का समाधान केवल कूटनीति तथा "विन-विन" समझौते से ही संभव है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ताकतें अमेरिका को फिर से युद्ध की ओर धकेलना चाहती हैं। अराघची ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और ईरान की चिंताएं तथा हित काफी हद तक समान हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश प्राचीन सभ्यताएं हैं और आपसी सम्मान, व्यापार तथा रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईरान ने भारतीय मानवीय सहायता और समर्थन की भी सराहना की। अराघची ने चाहबहार पोर्ट को भारत-ईरान सहयोग का प्रतीक बताते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसकी रफ्तार धीमी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया, काकेशस और यूरोप तक पहुंच का महत्वपूर्ण मार्ग बनेगा और भारत इसके विकास में अपनी भूमिका जारी रखेगा। अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं चाहता था और 2015 के परमाणु समझौते के जरिए उसने यह साबित भी किया। उन्होंने दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि वार्ता के दौरान ही अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमला किया तथा लगातार विरोधाभासी संदेश दिए। अराघची ने कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता पूरी तरह विफल नहीं हुई है लेकिन अमेरिका के व्यवहार और अविश्वास के कारण प्रक्रिया कठिन बनी हुई है। उन्होंने चीन की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि चीन पहले भी ईरान-सऊदी संबंध बहाल कराने में मदद कर चुका है और यदि वह कूटनीति को आगे बढ़ाने में सहायता करता है तो ईरान उसका स्वागत करेगा।

120 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले सज्जन सिंह पर गिरी गाज, भाजपा ने जिलाध्यक्ष पद से हटाया

संवाददाता

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन खपत कम करने की अपील की अवहेलना पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने अनुशासनहीनता पर भाजपा किसान मोर्चा भिंड जिला के अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव को उनके पद से हटा दिया है। दरअसल, मध्य प्रदेश के भिंड में भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सज्जन सिंह यादव को 120 गाड़ियों के काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन करना भारी पड़ा है। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता और प्रधानमंत्री के संदेश की अवहेलना मानते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटा दिया। सज्जन सिंह बुधवार को समर्थकों के साथ ग्वालियर से भिंड तक करीब 120 गाड़ियों के लंबे काफिले में पहुंचे थे। शहर में जगह-जगह समर्थकों ने उनका स्वागत किया। कई स्थानों पर फूल-मालाओं और नारों के बीच यह कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। सज्जन सिंह यादव भिंड जिले के मौ क्षेत्र के सक्रिय भाजपा नेता माने जाते हैं। वे पहले मौ मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी वंदना यादव वर्तमान में मौ नगर परिषद की अध्यक्ष हैं। संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद समर्थकों ने बड़े स्तर पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन यही प्रदर्शन अब उनके खिलाफ कार्रवाई का कारण बन गया। काफिले के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं। इसके बाद विपक्षी दलों ने भाजपा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मामला प्रदेश संगठन तक पहुंचा और गुरुवार को कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया कि 13 मई को ग्वालियर से भिंड तक निकाली गई रैली प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा बचत संबंधी अपील के विपरीत थी। इसे संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ माना गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर सज्जन सिंह यादव की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई। संगठन ने यह भी स्पष्ट संकेत दिया कि पार्टी में किसी भी पदाधिकारी को व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह किसी भी स्तर का नेता क्यों न हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने यह कार्रवाई पूरे संगठन को संदेश देने के उद्देश्य से की है। पार्टी यह दिखाना चाहती है कि प्रधानमंत्री के संदेशों की अनदेखी अब सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी बीते कई वर्षों से "प्रो-प्लैनेट लाइफस्टाइल", ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग पर जोर देते रहे हैं।

एल.आई.सी
भारतीय जीवन बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या समाधान हेतु संपर्क करें।
-भारत सिंह
मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जाँचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए दैनिक स्वर्णिम प्रदेश के अंतर्गत समाचार पत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियां, संस्थाए या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।

आज का राशिफल

मेष: निवेश के सुखद परिणाम आएंगे। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। किसी बड़ी बाधा के दूर होने से प्रसन्नता रहेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। पुराना रोग उभर सकता है। विवाद से क्लेश संभव है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें।

वृषभ: कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। व्यस्तता रहेगी। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरों से अपेक्षा पूर्ण नहीं होने से खिन्नता रहेगी। कार्य में विलंब होगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा।

मिथुन: व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। भाग्य का साथ रहेगा। व्यापार में वृद्धि के योग हैं। निवेश शुभ रहेगा। आय होगी। प्रमाद न करें। पुराने शत्रु परेशान कर सकते हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

कर्क: कारोबार में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। नए व्यापारिक अनुबंध होंगे। धनार्जन होगा। लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। शत्रु परास्त होंगे।

सिंह: कोर्ट व कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। कारोबार अच्छा चलेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्नता रहेंगे। किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद हो सकता है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें।

कन्या: धनलाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आय में निश्चितता होगी। ऐश्वर्य पर व्यय होगा। वाहन व मशीनरी आदि के प्रयोग में सावधानी रखें, विशेषकर स्त्रियां रसोई में ध्यान रखें। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। भाइयों का सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता बनी रहेगी। कुसंगति से हानि होगी।

तुला: जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। निवेशादि शुभ रहेंगे। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। स्त्री पक्ष से लाभ होगा। अज्ञात भय रहेगा। कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। शत्रु परास्त होंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

वृश्चिक: आय में वृद्धि होगी। भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। कोई बड़ा लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। भाग्य बेहद अनुकूल है, लाभ लें। चोट व रोग से बचें। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। लेन-देन में जल्दबाजी न करें।

धनु: भागदौड़ रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। किसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जल्दबाजी व लापरवाही न करें। अज्ञात भय सताएगा।

मकर: आज लेन-देन में विशेष सावधानी रखें। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। दुःखद समाचार मिल सकता है। किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद हो सकता है। व्यर्थ भागदौड़ होगी। कार्य में विलंब होगा। चिंता तथा तनाव रहेंगे। आय में निश्चितता रहेगी। पुराना रोग उभर सकता है।

कुंभ: पराक्रम बढ़ेगा। आय में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। किसी बड़े काम को करने में रुझान रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रशंसा प्राप्त होगी। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड से लाभ होगा। चोट व रोग से बचें। सुख के साधन जुटेंगे। घर में तनाव रह सकता है। प्रयास सफल रहेंगे।

मीन: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विवेक से कार्य करें। विरोधी सक्रिय रहेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में चैन रहेगा।

डिजिटल पेंशन सुधारों ने पेंशन वितरण को बनाया सुगम और पारदर्शी: डॉ. जितेन्द्र सिंह

संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्रीय लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दशक में देश के पेंशन प्रशासन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। अब यह प्रक्रियाबद्ध प्रणाली से विकसित होकर प्रौद्योगिकी-सक्षम, जन-केंद्रित तंत्र बन गया है, जो पेंशनभोगियों की गरिमा, पारदर्शिता और जीवन सुगमता पर केंद्रित है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन में आयोजित 16वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशनभोगियों को सरकारी सहायता लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदानकर्ताओं के रूप में देखना चाहिए, जिनका अनुभव, विशेषज्ञता और संस्थागत स्मृति राष्ट्रीय धरोहर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरल, सहानुभूति भरा और दायित्वपूर्ण पेंशन प्रशासन सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास किए हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि पेंशन अदालत व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी हितधारक साझा मंच पर बैठकर प्रायः मौके पर ही विवाद का सामूहिक समाधान करते हैं, बजाय इसके कि बातचीत केवल नियमित फाइल हस्तांतरण और आधिकारिक पत्राचार तक सीमित रहे। वर्ष 2014 से पेंशन सुधारों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समय ऐसा था जब पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग लोगों की ध्यान से काफी हद तक बाहर रहते हुए सीमित प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत संचालित होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में निरंतर सुधारों, डिजिटल उपायों और नागरिक-केंद्रित निर्णय द्वारा यह सरकार के सबसे सक्रिय विभागों में से एक बन गया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और डिजिटल तकनीक द्वारा जीवन प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने की सरकार की पहल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान अब जन भागीदारी पहल में बदल गया है और इससे वृद्ध पेंशनभोगियों की कठिनाइयों में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ से अधिक पेंशनभोगी पहले ही इस प्रणाली से लाभान्वित हुए हैं, जिससे पेंशन वितरण अधिक सुलभ, पारदर्शी और बाधा मुक्त हो गया है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री ने हाल के वर्षों में किए गए कई सुधारों का भी उल्लेख किया, जिनमें पारिवारिक पेंशन नियमों का सरलीकरण, गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित पुराने प्रावधानों को हटाना, तलाकशुदा और अलग हुई बेटियों से संबंधित प्रक्रियाओं में ढील और दिव्यांग आश्रितों के लाभ संबंधी सुधार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सुधार व्यावहारिक वास्तविकताओं और पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।

साल 2017 में यह पहल आरंभ होने के बाद से अब तक कुल 15 पेंशन अदालतें आयोजित की गई हैं, जिनमें 27,812 मामलों पर सुनवाई हुईं। इनमें से 19,948 शिकायतों का समाधान अदालतों में ही हो गया, जो 71.72 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर दर्शाता है। शेष मामलों का समाधान बाद में अंतर-मंत्रालयी समन्वय और समीक्षा तंत्र द्वारा किया गया। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 16वीं पेंशन अदालत में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों पर त्वरित निवारण हेतु सुनवाई हुई। कार्यक्रम के दौरान इस पहल की सफलता से संबंधी पर्चे जारी करने के साथ ही पेंशन अदालत के दिशा-निर्देश जारी किए गए और संयुक्त सचिव (पेंशन) ने डॉ. जितेंद्र सिंह के समक्ष महत्वपूर्ण पेंशन मामले प्रस्तुत किए। पेंशन अदालत ने 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 मामलों पर गौर किया, जो 15 अप्रैल, 2026 तक 45 दिनों से अधिक समय से लंबित थे। कुल शिकायतों में से अब तक 728 मामले का निपटारा हो चुका है। कार्यवाही के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह के समक्ष 16 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित कुल 26 महत्वपूर्ण मामले प्रस्तुत किए गए। इनमें रक्षा मंत्रालय के 12, गृह मंत्रालय के 8 और रेल मंत्रालय के 2 थे, जबकि शेष मामले अन्य मंत्रालयों और विभागों से संबंधित थे।

मध्य रेल आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई: 1367 दलाल गिरफ्तार, 43.67 लाख की प्रतिबंधित सामग्री जब्त

यात्रियों का 3.09 करोड़ का खोया सामान लौटाया, 'ऑपरेशन उपलब्ध', 'नारकोस', 'सतर्क' और 'अमानत' के तहत कार्रवाई

संवाददाता

मुंबई। मध्य रेल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने वर्ष 2026 के पहले चार महीनों में यात्री सुरक्षा, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और यात्रियों की संपत्ति की सुरक्षा को लेकर व्यापक अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। 'ऑपरेशन उपलब्ध', 'ऑपरेशन नारकोस', 'ऑपरेशन सतर्क' और 'ऑपरेशन अमानत' के तहत चलाए गए विशेष अभियानों में आरपीएफ ने 1367 दलालों (टाउट्स) को गिरफ्तार किया, 43.67 लाख मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री जब्त की तथा यात्रियों का 3.09 करोड़ मूल्य का खोया सामान वापस लौटाया। मध्य रेलवे के मुख्य जनसपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील निला ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया कि आरपीएफ द्वारा आरक्षित कोचों में अनधिकृत प्रवेश, तौलिया फैलाकर सीट कब्जाने और वास्तविक यात्रियों को परेशान करने वालों के खिलाफ 'ऑपरेशन उपलब्ध' चलाया गया। जनवरी से अप्रैल 2026 के दौरान मध्य रेल के सभी मंडलों में कुल 1377 मामले दर्ज किए गए और 1367 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 2.87 लाख का जुर्माना भी वसूला गया। सबसे अधिक कार्रवाई मुंबई मंडल में हुई, जहां 998 मामले दर्ज कर 986 लोगों को पकड़ा गया। इसके साथ ही 'ऑपरेशन नारकोस' के तहत रेलवे नेटवर्क के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान गांजा तस्करी के 13 मामले पकड़े गए और 21.92 लाख मूल्य का गांजा जब्त किया गया। इन मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नागपुर मंडल में सबसे अधिक 9 मामले सामने आए। 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत आरपीएफ ने प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों और अवैध शराब के खिलाफ भी व्यापक कार्रवाई की। चार मामलों में 16,286 किलोग्राम तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए, जिनकी कीमत 5.61 लाख बताई गई है। वहीं अवैध शराब के 28 मामलों में 9.45 लाख मिलीलीटर शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 16.14 लाख है। इन मामलों में कुल 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यात्रियों की सुविधा और विश्वास बनाए रखने के लिए 'ऑपरेशन अमानत' के अंतर्गत आरपीएफ ने खोए हुए सामान की बरामदगी और उसे वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने का अभियान भी चलाया। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच कुल 744 सामान बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 3.09 करोड़ है। आवश्यक सत्यापन के बाद यह सामान यात्रियों को वापस सौंप दिया गया। मुंबई मंडल में सबसे अधिक 1.11 करोड़ मूल्य का सामान लौटाया गया। डॉ. स्वप्नील निला ने कहा कि रेलवे परिसर और ट्रेनों का उपयोग किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। डॉ. निला ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल वैध टिकट के साथ यात्रा करें, अनधिकृत एजेंटों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस सामान की सूचना तुरंत आरपीएफ, जीआरपी, ड्यूटी पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों या रेलवे हेल्पलाइन १३९ पर दें।

प्रधानमंत्री के आह्वान पर उच्च शिक्षण विभाग की पहल, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जारी किए गए विशेष निर्देश

संवाददाता

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रहित और आर्थिक मजबूती के लिए किए गए आवाहन के अनुरूप महाराष्ट्र के उच्च शिक्षण संचालनालय ने राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, ईंधन बचत, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने, विदेश दौरों में कमी तथा जीवनशैली में बदलाव संबंधी निर्देश जारी किए हैं। यह जानकारी राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने दी। गुरुवार को मंत्री चंद्रकांत पाटील ने बताया कि इस संबंध में सभी विभागीय सह-संचालकों, उच्च शिक्षा विभाग तथा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को निर्देश भेजे गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि जहां संभव हो, निजी वाहनों का उपयोग कम कर मेट्रो रेल और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का अधिक इस्तेमाल किया जाए। इससे ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। संचालनालय ने पेट्रोल और डीजल के सीमित उपयोग तथा ऊर्जा बचत को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को कार पूलिंग जैसी अवधारणाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया है। निर्देशों के अनुसार, केवल अत्यंत आवश्यक या अपरिहार्य परिस्थितियों में ही विदेश दौरे किए जाएं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बैठकों को छोड़कर अन्य बैठकों का आयोजन ऑनलाइन माध्यम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने पर बल दिया गया है। उच्च शिक्षण संचालनालय ने कहा है कि देश की आयात निर्भरता और वित्तीय घाटा कम करने के लिए अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाने जैसे कदम अपनाने की भी सलाह दी गई है। राज्य की सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को इन निर्देशों को गंभीरता से लागू करने के लिए कहा गया है। शैक्षणिक परिसरों में इस विषय पर चर्चा सत्र, जागरूकता अभियान और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों और संस्थानों को तत्काल निर्देश जारी कर कार्यवाही रिपोर्ट उच्च शिक्षण संचालनालय को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

ठाणे क्राइम ब्रांच ने 'लेडी गैंग' का किया भंडाफोड़, 37 लाख के सोने के गहने बरामद

संवाददाता

ठाणे। ठाणे में क्राइम ब्रांच यूनिट-1 ने सार्वजनिक परिवहन में चोरी करने वाली एक कुख्यात 'लेडी गैंग' का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस कार्रवाई में दो महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 25 तोला सोने के गहने बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 37.19 लाख रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई से कालवा, राबोडी, नौपाड़ा और ठाणे शहर समेत विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज चोरी के नौ लंबित मामलों का खुलासा हो गया है। पुलिस के अनुसार, यह गैंग खासतौर पर भीड़भाड़ वाली बसों में सफर करने वाले यात्रियों को निशाना बनाती थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब 72 वर्षीय अंजनी दत्तात्रेय सूर्यवंशी ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि खरेगांव नाका से ओजोन वैली के बीच बस यात्रा के दौरान उनका पर्स चोरी हो गया, जिसमें करीब 12 तोला सोने के गहने रखे थे। आरोप है कि बस में मौजूद तीन महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान इस प्रकार हुई—संगीता दशरथ पिठकर (45) व सुरेखा बजरंग गायकवाड़ (47)। दोनों आरोपी मुंबई के मुलुंड पश्चिम क्षेत्र की निवासी बताई जा रही हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने पिछले दो वर्षों से बस यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।

यह पूरी कार्रवाई डीसीपी (क्राइम) अमरसिंह जाधव और एसीपी शेखर बगाडे के मार्गदर्शन में की गई। वहीं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सचिन गायकवाड़, पीएसआई प्रकाश शिरसाट और उनकी टीम ने जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अब इस गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की आगे जांच जारी है।

एनेक्स मॉल में लगी आग, मची अफरा-तफरी

संवाददाता

मुंबई। मुंबई के बोरीवली पूर्व इलाके में स्थित एनेक्स मॉल में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास स्थित इस व्यस्त व्यावसायिक परिसर में खरीदारी करने आए लोगों और स्थानीय निवासियों में घटना के बाद दहशत का माहौल देखा गया। अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की सूचना दोपहर करीब 2:03 बजे मिली, जिसके तुरंत बाद मुंबई फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सिद्धार्थ नगर स्थित एनेक्स मॉल की पहली मंजिल पर बने एक होटल में आग लगी थी। कुछ ही देर में इमारत से घना धुआं निकलने लगा, जिससे मॉल में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुंबई फायर ब्रिगेड ने दोपहर 2:07 बजे आग को 'लेवल-1' श्रेणी घोषित किया। आग को फैलने से रोकने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां और आपातकालीन टीमें मौके पर तैनात की गईं। मॉल में आग का अलार्म बजते ही लोग और कर्मचारी तेजी से बाहर निकलते दिखाई दिए। पुलिसकर्मियों और वार्ड अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। घटना के कारण मॉल के पास स्थित वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। दमकल वाहनों और बचाव कार्य के चलते सड़क के एक हिस्से पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। फिलहाल राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के घायल होने या किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र बनेगा भारत-अफ्रीका व्यापार का वैश्विक केंद्र: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सिडको और AIEF के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता, खारघर में बनेगा अफ्रीका-भारत व्यापार केंद्र

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार की उपस्थिति में सिडको और अफ्रीका इंडिया इकॉनॉमिक फाउंडेशन (AIEF) के बीच अफ्रीका-भारत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गुरुवार को मंत्रिमंडल सभागार में आयोजित इस बैठक में नगर विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सिडको के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विजय सिंघल, सह-प्रबंध निदेशक शांतनु गोयल, AIEF के अध्यक्ष डॉ. जी. रथिनवेलू और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

खारघर में विकसित होगा अफ्रीका-भारत अंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र

सिडको द्वारा नवी मुंबई के खारघर स्थित इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क में अफ्रीका-भारत अंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र (AIIDZ) विकसित किया जाएगा। यह परियोजना भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाला एक वैश्विक केंद्र बनेगी। करीब 20 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली इस परियोजना में कमर्शियल टॉवर, कन्वेंशन सेंटर, होटल, सर्विस्ड अपार्टमेंट, सांस्कृतिक केंद्र और रिटेल हब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। परियोजना अगले पांच से छह वर्षों में पूरी तरह कार्यान्वित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री फडणवीस बोले — 'महाराष्ट्र को मिलेगा वैश्विक पहचान'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अफ्रीका-भारत व्यापार केंद्र महाराष्ट्र को भारत-अफ्रीका संबंधों के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना व्यापार, निवेश, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर पैदा करेगी तथा ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका को और मजबूत बनाएगी।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया विश्वस्तरीय परियोजना

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि खारघर में बनने वाला यह अंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र वैश्विक व्यापारिक संबंधों को गति देने वाली विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति इसे अंतरराष्ट्रीय निवेश और व्यापार के लिए आदर्श केंद्र बनाएगी।

MSME और रोजगार को मिलेगा बड़ा लाभ

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा कि यह परियोजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए नए अवसर पैदा करेगी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और वैश्विक निवेश आकर्षित होगा।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

- 54 अफ्रीकी देशों और भारतीय हितधारकों के लिए स्थायी कार्यालय
- 2.5 लाख वर्ग फुट का प्रदर्शनी क्षेत्र
- 5,000 से 6,000 क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर
- होटल और सर्विस्ड अपार्टमेंट
- सांस्कृतिक एवं रिटेल हब
- अफ्रीका-इंडिया बायो डोम
- वर्षभर 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने की योजना

मुंबई बनेगा ग्लोबल साउथ का प्रवेशद्वार

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और जेएनपीटी बंदरगाह के निकट स्थित यह परियोजना मुंबई को एशिया और ग्लोबल साउथ के प्रमुख आर्थिक प्रवेशद्वार के रूप में स्थापित करेगी। परियोजना से विदेशी निवेश, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित गांधी-मंडेला कन्वेंशन सेंटर भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सांस्कृतिक और संस्थागत संबंधों को मजबूत करेगा। यह पहल भारत को अफ्रीका के विश्वसनीय और रणनीतिक भागीदार के रूप में और अधिक सशक्त बनाएगी।

30 जून 2026 से पहले संपत्ति कर भरने पर 5 प्रतिशत की छूट, एमबीएमसी की नागरिकों से अपील

संवाददाता

मुंबई। मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) ने सभी संपत्ति धारकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का संपूर्ण संपत्ति कर 30 जून 2026 से पहले जमा करने पर नागरिकों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। महानगरपालिका ने यह योजना राजस्व वृद्धि के साथ-साथ नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की है। महानगर पालिका प्रशासन ने बताया कि संपत्ति कर नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत है, जिसका उपयोग शहर में सड़क निर्माण, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक सुविधाएं, बुनियादी ढांचा विकास और विभिन्न नागरिक सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए किया जाता है। इसलिए सभी नागरिकों से समय पर संपत्ति कर जमा कर महानगरपालिका का सहयोग करने की अपील की गई है। नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन कर भुगतान की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। नागरिक मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट, 'My MBMC' मोबाइल ऐप तथा व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा के माध्यम से घर बैठे सुरक्षित और सरल तरीके से संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक +91 9967611234 नंबर पर 'Hi' संदेश भेज सकते हैं। महानगरपालिका ने यह भी बताया कि नागरिक चालू वर्ष का कर बिल भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अंतिम तिथि तक भुगतान लंबित न रखने और 5 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने की अपील की है।

मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर चांदी से भरी वैन पलटी, 17.66 करोड़ की खेप सुरक्षित

संवाददाता

मुंबई। मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर स्थित चारोटी फ्लाईओवर के पास शुक्रवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया, जब लगभग 17.66 करोड़ रुपये मूल्य की चांदी की ईंटें ले जा रही एक वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

600 किलो चांदी लेकर गुजरात जा रही थी वैन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वैन में करीब 600 किलोग्राम चांदी लदी हुई थी। यह खेप नकोडा बुलियन से गुजरात भेजी जा रही थी। चांदी को मोदी संस लिमिटेड तक पहुंचाया जाना था। बताया जा रहा है कि वाहन मुंबई से वापी की ओर जा रहा था, तभी चारोटी फ्लाईओवर पार करते

समय चालक ने नियंत्रण खो दिया और वैन हाईवे पर पलट गई।

ड्राइवर घायल, बड़ा नुकसान टला

हादसे में वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चालक को केवल मामूली चोटें आईं। मौके पर ही उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस दुर्घटना में किसी अन्य व्यक्ति के घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।

दुर्घटना के बाद हाईवे के उस हिस्से पर यातायात प्रभावित हो गया। राहगीरों और वाहनों की भीड़ जमा होने लगी, जिसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कासा पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया।

चांदी की खेप पूरी तरह सुरक्षित

चूंकि वाहन में करोड़ों रुपये की चांदी मौजूद थी, इसलिए पुलिस ने किसी भी संभावित चोरी या अफरा-तफरी को रोकने के लिए आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चांदी की ईंटों को वाहन से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि पूरी खेप सुरक्षित मिली है और उसका पूरा हिसाब-किताब भी मिल गया है।

हादसे के कारणों की जांच जारी

प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार, यांत्रिक खराबी या सड़क की स्थिति को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस अब वाहन की तकनीकी जांच भी करवा रही है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। कई घंटों तक चले बचाव अभियान के बाद हाईवे पर यातायात धीरे-धीरे सामान्य किया गया।

Special Intensive Revision of Electoral Roll in Odisha to Begin from May 30

BHUBANESWAR: Election Commission of India will launch the Special Intensive Revision (SIR) of the electoral roll in Odisha from May 30, 2026, with Booth Level Officers (BLOs) set to carry out door-to-door verification across the state till June 28 as part of the voter list revision exercise. Chief Electoral Officer R S Gopalan said the final electoral roll will be published on September 6, 2026, after completion of verification, correction and grievance redressal procedures.

Addressing the media, Gopalan said July 1, 2026, has been fixed as the qualifying date for inclusion of eligible voters who have attained the age of 18 years.

He informed that the revision activity will formally commence from May 20. 'From May 30 to June 28, BLOs will visit households and distribute enumeration forms. The forms will be collected after being duly filled,' he said. The draft electoral roll will be published on July 5, following which a nearly month-long period will be provided for filing objections and claims. The final voter list will then be released on September 6, he added. The CEO further stated that two copies of the enumeration form will be issued during the verification process. One signed copy will remain with the voter as proof, while the other will be submitted to the BLOs.

He said notices would be issued to individuals with minor discrepancies in their details, including incorrect dates of birth or errors in parents' names. Such voters will be required to submit supporting documents, and all pending issues are expected to be resolved by September 2.

According to Gopalan, more than 9 lakh names have been deleted from the voter list over the past nine months due to migration and deaths. 'At present, Odisha has around 3.34 crore voters. Form 6 will be used for inclusion of new voters in the electoral roll,' he said. On the issue of alleged inclusion of non-citizens in the voter list, Gopalan said that any person found ineligible or improperly enrolled would be removed from the electoral roll, irrespective of nationality.

Odisha Government Directs Expedited Transfer and Rotation of Revenue Administration Staff

BHUBANESWAR: 15 May (H.S.) The Odisha Government has directed all district collectors to strictly implement the transfer and rotation process for ministerial and field-level employees in the Revenue Administration. Arvind Padhee, Additional Chief Secretary of the Revenue and Disaster Management Department, has communicated to all district collectors, instructing them to ensure the timely execution of this process.

According to the directive, employees including Section Officers (SO), Senior Revenue Assistants (SRA), Junior Revenue Assistants (JRA), and field-level staff such as Revenue Supervisors (RS), Revenue Inspectors (RI), Assistant Revenue Inspectors (ARI), and Amins who have served in the same office for over three years must be transferred or rotated without exception.

The government stated that this move aims to enhance administrative efficiency, transparency, and accountability in district collectorates, sub-collector offices, block offices, and tehsil offices across the state.

Taking serious note of pending transfer cases in several districts, the state government has issued strict instructions to complete the entire transfer and rotation exercise during the current transfer season, by June 15, 2026.

The directive further emphasizes that transfers of all officers and employees who have served for over three years in the same office or establishment must be executed in accordance with the government's existing policies and guidelines.

District administrations have also been instructed to submit a detailed compliance report to the department immediately after completing the transfer process.

WE MUST NOT FALL PREY TO THE OPPOSITION'S NEGATIVE POLITICS AND NARRATIVE: UP CM

MAHARAJGANJ: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath advised people on Friday not to fall for the opposition's bad tactics and narrative, instead supporting Prime Minister Narendra Modi and his call to reduce fuel use and other expenditures. He was addressing during the inauguration and foundation-laying ceremony for a number of public welfare projects costing more than Rs 208 crore in Maharajganj. In a post on X, UP CM remarked, 'In Maharajganj district, the inauguration/foundation stone laying ceremony of different public benefit projects totaling about Rs 208 crore. As friendly nations, India and Nepal have a common heritage. When there was an issue. I was always there among you, and Bharatiya Janata Party and Hindu Yuva Vahini activists were always visible working for your concerns.

Maharajganj has also witnessed some changes. There is now also a medical college here. The first requirement for development is access to decent roadways. The BJP's double-engine administration is listening to the concerns of the poor while simultaneously offering remedies. You have just one vote. When thrown in the correct area, it promotes growth. However, when we cast our votes based on caste, area, or nepotism, we end up with mafias, chaos, and thugs.' In another post on X, UP CM added, 'The Shri Ram Mandir at Shri Ayodhya Dham and the Kashi Vishwanath Dham were built over opposition from SP, BSP, and Congress members. That is why the Bengali people have permanently uprooted them. We must avoid falling victim to the opposition's negative politics and narrative. We must safeguard the country's money and rescue our country from this worldwide disaster. Under the effective leadership of Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji, Maharajganj has seen a new picture of growth and transformation since the double-engine government began operating in Uttar Pradesh. Today, 79 development projects worth over Rs. 208 crore in the district were inaugurated and the foundation stone was laid as part of the ongoing transition. On this occasion, approval letters and toolkits were delivered to recipients of several departments' welfare initiatives. There is complete faith that Maharajganj's progress will continue without interruption, faltering, or tired. Congratulations to the citizens of the district.' He stated that the confrontation in West Asia between the United States and Iran has had an influence on oil supply. The formerly accessible supply of fuel, and LPG has been drastically impacted. Every day, the government incurs losses equal to thousands of crores. This loss is the responsibility of the nation, and by 'nation' we mean the people. What is then the public's responsibility? Every individual is responsible for standing with the government and, by doing so, uniting the nation. He went on to say that diesel, petrol, and LPG costs had skyrocketed in key global markets.

आबकारी घोटाळा प्रकरण : न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांची सुनावणीतून माघार

नवी दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाळा प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी सीबीआयच्या अपील याचिकेच्या सुनावणीतून स्वतःला बाजूला घेतले आहे.

मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या विरोधात नियोजित पद्धतीने मोहीम राबवून न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे आता त्या आम आदमी पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांविरोधात न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरू करणार आहेत. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज आणि विनय मिश्रा यांच्यासह इतर काही जणांनी सोशल मीडियावर आणि सार्वजनिक मंचांवर न्यायालयाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी मोहीम चालवली.

न्यायालयाच्या मते, ही 'निष्पक्ष टीका' नसून न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होता. न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाल्या की कोणत्याही न्यायालयीन आदेशावर टीका करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र, एखाद्या न्यायाधीशाला पक्षपाती ठरवण्यासाठी संघटित मोहीम राबवणे हे न्यायालयीन अवमानाच्या कक्षेत येते. त्यांनी नमूद केले की त्यांच्या विरोधातील व्हिडिओ, पोस्ट आणि विधाने ही त्यांना खटल्याच्या सुनावणीतून दूर करण्याच्या उद्देशाने प्रसारित करण्यात आली.

न्यायालयाने विशेषतः त्या व्हिडिओ आणि सोशल मीडिया पोस्टचा उल्लेख केला ज्यामध्ये न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यावर राजकीय झुकावाचे आरोप करण्यात आले होते. त्यांनी सांगितले की वाराणसीतील एका विद्यापीठातील त्यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ एडिट करून चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आला. न्यायालयाने याला न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला धक्का देण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले.सुनावणीदरम्यान तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली की त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवावी. त्यांनी म्हटले की एखाद्या पक्षाला न्यायालयीन आदेशाबाबत आक्षेप असल्यास त्यासाठी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हा घटनात्मक मार्ग आहे, सार्वजनिक मोहीम चालवणे नव्हे. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी असेही सांगितले की या मोहिमेत सहभागी झालेल्या आणि न्यायालयाविरोधात अपमानास्पद सामग्री प्रसारित करणाऱ्या काही यूट्यूबर्स आणि सोशल मीडिया खात्यांविरोधातही कारवाईचा विचार केला जात आहे. संबंधित सामग्री गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, मुख्य प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात आले असून आता या प्रकरणाची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठासमोर होणार आहे. तर न्यायालयीन अवमान प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती शर्मा स्वतः करणार आहेत.

देशात पेट्रोल डिझेल आणि सीएनजीची दरवाढ, नवे दर लागू

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 3.25 रुपयांची वाढ जाहीर केली असून, त्यामुळे महागाईचा आणखी एक मोठा झटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. नवीन दर शुक्रवारपासून लागू करण्यात आले आहेत. राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर ९४.७७ रुपयांवरून ९७.७७ रुपये प्रतिलिटर झाला असून, डिझेल ८७.६७ रुपयांवरून ९०.६७ रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचले आहे. मुंबईत पेट्रोल १०६.६८ रुपये तर डिझेल ९३.१४ रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जात आहे. कोलकाता आणि चेन्नईमध्येही इंधन दरांनी शंभरीच्या जवळपास मजल मारली आहे.आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळसारख्या राज्यांमध्ये पेट्रोलचे दर ११० रुपयांच्या पुढे गेले असून, अनेक राज्यांत डिझेलही १०० रुपयांच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे.दरम्यान, दिल्ली-एनसीआर परिसरात सीएनजीच्या दरातही प्रतिकिलो २ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे ऑटो, कॅब

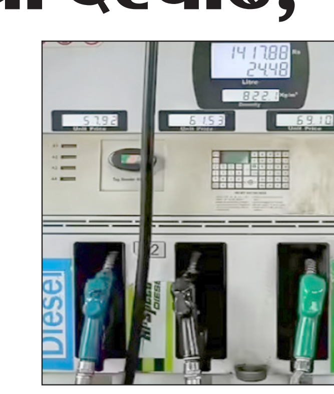

आणि खासगी वाहनांच्या खर्चात वाढ होणार असून त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या बजेटवर होणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातही सीएनजीचे दर ८४ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत वाढले आहेत. महागाईचा आणखी एक फटका म्हणजे मदर डेअरीने दुधाच्या किमतीत प्रतिलिटर २ रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजारातील परिस्थितीमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये विविध प्रकारच्या दुधाचे नवे दर लागू झाले आहेत. प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे नवे दर (प्रति लिटर)

नवी दिल्ली – ९७.७७ रुपये
मुंबई – १०६.६८ रुपये
कोलकाता – १०८.७० रुपये
चेन्नई – १०३.६७ रुपये
हैदराबाद – ११०.८९ रुपये
जयपूर – १०७.९७ रुपये
पटणा – १०८.५५ रुपये
तिरुवनंतपुरम – ११०.५८ रुपये

पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा संकट तीव्र झाले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, ब्रेंट कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. तथापि, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी देशात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. वाढत्या जागतिक संकटातही भारताने पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा अखंड पुरवठा कायम ठेवला असल्याचा दावा त्यांनी केला.

अमरावतीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 'एल निनो'च्या पार्श्वभूमीवर आढावा

अमरावती: 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत जिल्ह्यातील पाणी टंचाई, जलसंधारण, शेती आणि चाऱ्याच्या उपलब्धतेबाबत विविध विभागांकडून सद्यस्थिती जाणून घेत आगामी काळातील उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीला प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर घ्यार उपस्थित होते. 'एल निनो'मुळे पाणी प्रभावीत होणार आहे. त्यामुळे उपाययोजना म्हणून जलसंधारणाच्या कामावर भर देण्यात येणार आहे. यावेळी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील पाण्याच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी यांनी जलयुक्त शिवार अभियानाची सद्यस्थिती, तलाव आणि नाल्यांमधील गाळ काढणे, कालवा दुरुस्ती, चेक डॅमची कामे आणि नाला खोलीकरणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्व जलसंधारण कामांचे मॅपिंग करण्याच्या सूचना दिल्या.ग्रामीण व शहरी भागातील

पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई लक्षात घेऊन पाणी पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणांनी नियोजन करावे. ग्रामीण भागात टंचाईवर मात करण्यासाठी सार्वजनिक बोअरवेलवर सोलर पंप बसवण्याच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

जिल्ह्यातील जलाशयांमधील उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी प्राधान्याने उपयोगात आणावे. शहरी भागात नळजोडणीची तपासणी करून पाणीगळती तात्काळ दुरूस्त करण्यात यावी. याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला कळविण्यात यावे, अशा सूचना दिल्या.

सिंचनासाठी पाण्याचा वापर करताना सूक्ष्म नियोजन करावे. कालवा दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावेत. कृषी विभागाने शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन करावे. पीक विम्याची सद्यस्थिती आणि शेततळ्यांच्या कामांचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी चाऱ्याची सद्यस्थिती तपासून आवश्यक ते नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. याबाबत पशूसंवर्धन विभागाने जुलैपर्यंत चाऱ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पुरेसा चारा उपलब्ध होणार आहे. तसेच शासकीय जमिनीवर चारा लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

जलसंधारणाच्या कामातून भूजल पातळी वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. प्रामुख्याने रिचार्ज शाफ्टच्या कामाचे नियोजन करावे. तसेच नवीन बोअरवेलच्या कामांवर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रोजगार हमी योजनेतून 'गाव तिथे जलसंधारण कामे' राबवली जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने शेततळे, पाझर तलाव, नाला खोलीकरण आणि गाळ काढणे, तसेच बोअरवेल आणि विहीर पुनर्भरणाची कामे हाती घेण्यात यावी. वन विभागानेही पाणी साठविण्यासाठी जागा निवडून कामे सुरू करावीत, असे निर्देश देण्यात आले.

बंगाल में रिलीज होगी 'आखिरी सवाल', मिथुन बोले- अब आएगी 'द बंगाल फाइल्स'

मुंबई। निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग की हिंदी फिल्म 'आखिरी सवाल' की पश्चिम बंगाल में रिलीज की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म का ट्रेलर भी मीडिया और दर्शकों को दिखाया गया। पूरा कार्यक्रम बंगाल के बदले हुए राजनीतिक माहौल और फिल्म की संवेदनशील विषयवस्तु को लेकर चर्चाओं में रहा। फिल्म की कहानी बाबरी मस्जिद विध्वंस, आरएसएस की भूमिका और इससे जुड़े राजनीतिक-ऐतिहासिक विमर्श पर आधारित है। फिल्म में संजय दत्त महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि, संजय दत्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। कार्यक्रम में भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती उपस्थित रहे। उनके बेटे नमाशी चक्रवर्ती फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं। अभिनेत्री समीरा रेड्डी भी फिल्म का हिस्सा हैं। निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग ने बताया कि आने वाले समय में मिथुन चक्रवर्ती और नमाशी चक्रवर्ती पहली बार साथ में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। नई फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है और चुनाव के बाद मिथुन दा की तारीखों का इंतजार था। ट्रेलर दिखाए जाने पर दर्शकों और समर्थकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसे लेकर हम उत्साहित हैं।

मंच से कहा गया कि 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्मों को पहले बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया गया था, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद 'आखिरी सवाल' बंगाल में रिलीज होने जा रही है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अब सिर्फ 'आखिरी सवाल' ही नहीं, बल्कि 'द बंगाल फाइल्स' भी बंगाल में रिलीज होगी। उन्होंने फिल्म को 'वो सच्चाई' बताया जिसे देश को जानना चाहिए। मिथुन ने कहा कि बंगाल में अब 'सोनार बांग्ला' का सपना साकार होगा और राज्य विकास की नई राह पर चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वर्षों तक बंगाल की राजनीति को ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर चलाया गया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने साबित कर दिया है कि 'मुस्लिम वोट के बिना भी बंगाल में सरकार बन सकती है'। चुनाव बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से जुड़े एक सवाल के जवाब में मिथुन ने कहा कि जनता अपना फैसला दे चुकी है, अब उनके सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता।

कान्स 2026 के लिए रवाना हुईं अदिति राव हैदरी

मुंबई। फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में चल रहे कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में इस बार बॉलीवुड सितारों का खास जलवा देखने को मिल रहा है। आलिया भट्ट, उर्वशी रौतेला और तारा सुतारिया के बाद अब एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी इस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुकी हैं। मुंबई एयरपोर्ट से उनका वीडियो और तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कान्स 2026 के लिए रवाना होने से पहले अदिति राव हैदरी बेहद स्टाइलिश लेकिन सिंपल अंदाज में नजर आईं। उन्होंने गोल्डन ब्राउन ट्रेंच कोट के साथ बेज फिटेड टॉप और डेनिम जींस कैरी की थी। उनके इस क्लासी और एलिगेंट एयरपोर्ट लुक को फैंस ने काफी पसंद किया। अदिति ने अपने पूरे लुक को मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ कंप्लीट किया था। उनका यह सटल फैशन स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अदिति ने एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीं। इन तस्वीरों पर उनके पति और अभिनेता सिद्धार्थ का कमेंट सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। सिद्धार्थ ने कमेंट करते हुए लिखा कि गोल्डन गर्ल। सिद्धार्थ का यह प्यार भरा कमेंट देखते ही फैंस खुश हो गए और दोनों की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ करने लगे। सोशल मीडिया पर लोग इस कपल को बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स में से एक बता रहे हैं।

अदिति राव हैदरी अपने रॉयल और ट्रेडिशनल फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई इंटरनेशनल इवेंट्स में अपने स्टाइल से लोगों का दिल जीता है। ऐसे में अब फैंस को उनके कान्स 2026 रेड कार्पेट लुक का बेसब्री से इंतजार है। फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भी अदिति भारतीय और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत मिश्रण पेश कर सकती हैं।

प्रभास का वायरल 'स्पिरिट' लुक असली नहीं

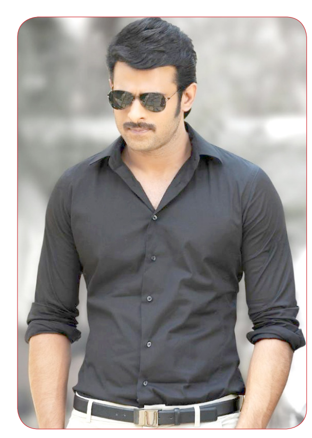

मुंबई। साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ जहां उनकी फिल्म 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, वहीं दूसरी ओर फैंस अब उनकी अपकमिंग फिल्मों 'फौजी' और 'स्पिरिट' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रभास की एक तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी, जिसे लेकर दावा किया गया कि यह उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म स्पिरिटके सेट से लीक हुई है। तस्वीर सामने आते ही फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। वायरल फोटो में प्रभास सफेद शर्ट और धोती पहने नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में शॉटगन दिखाई दे रही है, जबकि लंबे बाल, घनी दाढ़ी और चश्मे वाला लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

कई फैन पेज इस तस्वीर को शेयर करते हुए दावा कर रहे थे कि यह 'स्पिरिट' में प्रभास का नया अवतार है। फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त उत्साह बना हुआ है, ऐसे में इस तस्वीर ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी। हालांकि कुछ लोगों को तस्वीर देखकर शक हुआ और फिर इसकी सच्चाई सामने आने लगी। जांच के बाद पता चला कि प्रभास की वायरल तस्वीर असली नहीं बल्कि AI जनरेटेड है।

प्रभास की वायरल फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है और इसका फिल्म 'स्पिरिट' के सेट या शूटिंग से कोई लेना-देना नहीं है। शुरुआत में कई लोग इस तस्वीर को असली समझ बैठे थे, लेकिन बाद में सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीर की डिटेल्स देखकर साफ कर दिया कि यह फेक इमेज है। फिलहाल फिल्म के सेट से प्रभास का कोई आधिकारिक लुक सामने नहीं आया है।

संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही 'स्पिरिट' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। फिल्म में प्रभास मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जबकि तृप्ति डिमरी फीमेल लीड के तौर पर नजर आएंगी। वहीं विवेक ओबेरॉय फिल्म में विलेन के रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म को T-Series और भद्रकाली पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मार्च 2027 में रिलीज हो सकती है।

खट्टे-मीठे स्वाद के लिए सब्जियों में मिलाएं गुड़ का तड़का

गुड़ भारतीय रसोई का ऐसा खजाना है जो स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखता है। खासकर जब इसे सब्जियों में डाला जाए तो सब्जी का खट्टा-मीठा स्वाद हर किसी को लाजवाब लगता है। गुड़ से बनी सब्जियां उत्तर भारत से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक बेहद पसंद की जाती हैं। ये न सिर्फ खाने में जायकेदार होती हैं, बल्कि पाचन को दुरुस्त रखने, शरीर को एनर्जी देने और खून को शुद्ध करने में भी मदद करती हैं।

आइए जानते हैं गुड़ से बनी कुछ सब्जियों के बारे में, जो आपके घर में भी हर किसी को खूब भाएंगी।

गुड़ मिलाकर बेहद स्वादिष्ट लगती हैं ये सब्जियां

कद्दू की सब्जी- उत्तर भारत में कई जगहों पर कद्दू की सब्जी में गुड़ डालकर बनाई जाती है। इसमें हींग, जीरा, अदरक-लहसुन और हल्की-सी अमचूर के साथ गुड़ डालने पर यह खट्टा-मीठा जायका देती है। ये पूरी या पराठे के साथ खूब पसंद की जाती है।

करेला गुड़ वाली सब्जी- करेले की कड़वाहट हर किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन इसमें गुड़ डालकर पकाने से इसका स्वाद निखर जाता है। गुड़ करेला की

कड़वाहट को संतुलित करता है और यह सब्जी न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि डायबिटीज कंट्रोल में भी मददगार होती है।

टिंडे की सब्जी- टिंडे की सब्जी को अक्सर लोग फीका मानते हैं, लेकिन इसमें गुड़ और इमली डालकर बनाई जाए तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। यह मसालेदार, खट्टा-मीठा स्वाद परिवार के हर सदस्य को पसंद आएगा।

- **ग्वार फली की सब्जी-** गुजरात और महाराष्ट्र में ग्वार फली को गुड़ डालकर बनाया जाता है। इसमें मूंगफली पाउडर और मसालों के साथ गुड़ डालने पर यह सब्जी बेहद जायकेदार बनती है और चावल या रोटी दोनों के साथ परफेक्ट लगती है।
- **लौकी की सब्जी-** लौकी की सब्जी को अक्सर लोग उबाऊ मानते हैं, लेकिन इसमें गुड़ और टमाटर डालकर बनाई जाए तो इसका स्वाद बदल जाता है। हल्की-सी खटास और मिठास इसे डिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाती है।
- **बैंगन की सब्जी-** बैंगन की सब्जी को खासतौर पर महाराष्ट्र में गुड़ डालकर पकाया जाता है। मसालों, नारियल और मूंगफली के साथ गुड़ मिलाकर यह सब्जी गाढ़ी और लाजवाब बनती है। इसे खासकर ज्वार-भाखरी या बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है।

गुड़ से बनी ये सब्जियां सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती हैं। इनमें खट्टे-मीठे स्वाद का ऐसा कॉम्बीनेशन मिलता है जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे। इसलिए अगली बार जब घर में कोई खास डिनर या लंच बनाना चाहें, तो इनमें से किसी एक सब्जी को जरूर ट्राई करें।

लौंग से हल्दी तक, दांत दर्द में असरदार हैं ये घरेलू नुस्खे

दांत का दर्द एक ऐसी समस्या है जो न केवल आपके खान-पान बल्कि आपके पूरे दिन की कार्यक्षमता को प्रभावित कर देती है। कभी ठंडे-गरम से होने वाली झनझनाहट, तो कभी मसूड़ों में संक्रमण या सड़न के कारण उठने वाला तेज दर्द इंसान को बेचैन कर देता है। अक्सर यह दर्द रात के समय या ऐसे वक्त पर उठता है जब डेंटिस्ट के पास जाना तुरंत संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में बताए गए प्राकृतिक उपाय किसी वरदान से कम साबित नहीं होते।आइए जानते हैं रसोई में मौजूद उन चीजों के बारे में जो आपके दांतों के लिए पेनकिलर का काम कर सकती हैं।

लौंग

आयुर्वेद में लौंग को दांत दर्द की सबसे अचूक दवा माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो लौंग में यूजेनॉल नामक एक सक्रिय तत्व पाया जाता है। यह तत्व एक बेहतरीन प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। जब आप दर्द वाले दांत के नीचे लौंग दबाकर रखते हैं या कॉटन की मदद से लौंग का तेल लगाते हैं तो यह उस हिस्से की नसों को हल्का सुन्न कर देता है जिससे दर्द का अहसास तुरंत कम हो जाता है। हालांकि ध्यान रहे कि लौंग का तेल बहुत शक्तिशाली होता है इसलिए इसका उपयोग सीमित मात्रा में ही करें।

नीम

भारत में सदियों से दांतों की सफाई के लिए नीम की दातुन का प्रयोग किया जाता रहा है। नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के हानिकारक कीटाणुओं का सफाया करते हैं। यह न केवल दर्द में राहत देता है, बल्कि मसूड़ों को मजबूत भी बनाता है। नीम मुंह के पीएच लेवल को संतुलित रखने में मदद करता है जिससे एसिडिटी कम होती है और कैविटी बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

हल्दी

हर किचन में पाई जाने वाली औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी कई समस्याओं को कम करती है। इसमें मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक होता है। यदि दांत दर्द के साथ मसूड़ों में सूजन आ गई है तो हल्दी को थोड़े से सरसों के तेल के साथ मिलाकर प्रभावित हिस्से पर मालिश करने से काफी लाभ होता है। यह न केवल दर्द को खींच लेती है बल्कि संक्रमण को फैलने से भी रोकती है।

सड़न रोकने का तरीका

मुलेठी का उपयोग अक्सर गले की खराश के लिए किया जाता है लेकिन यह ओरल हेल्थ के लिए भी उत्कृष्ट है। मुलेठी की जड़ में मौजूद तत्व दांतों की सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं। इसका पाउडर एक प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करता है जो दांतों की सतह पर जमा प्लाक को साफ कर मसूड़ों को राहत पहुँचाता है।

नमक पानी के गरारे

नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला करना एक बेहतरीन नेचुरल डिसइंफेक्टेंट प्रक्रिया है। नमक पानी मसूड़ों की सूजन को कम करता है और दांतों के बीच फंसे भोजन के कणों को निकाल देता है। यह मुंह के छालों और संक्रमण को दूर करने का सबसे सुलभ तरीका है। ये घरेलू उपाय आपको तुरंत राहत देने में मदद करेंगे। हालांकि यदि दर्द लगातार बना रहे या मसूड़ों से खून आने की समस्या हो तो विशेषज्ञ डेंटिस्ट से परामर्श लेना अनिवार्य है। अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखें और दिन में दो बार ब्रश जरूर करें।

गिग इकोनॉमी ने युवाओं को दिया अपनी शर्तों पर काम करने का मौका

भारत में तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के दौर में गिग वर्क युवाओं के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। पारंपरिक नौकरी के साथ-साथ या उसके बिना भी, आज बड़ी संख्या में युवा रैपिडो , जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कमाई के नए रास्ते बना रहे हैं। खास बात यह है कि अब कमाई के लिए बड़ी डिग्री या भारी निवेश की जरूरत नहीं, बल्कि एक स्मार्टफोन और बाइक भी आपको रोजगार दे सकती है।

सरल शुरुआत व कम निवेश

गिग वर्क में काम शुरू करना बेहद आसान है। इसके लिए आपके पास एक स्मार्टफोन, इंटरनेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और एक बाइक या स्कूटी होना जरूरी है। जिनके पास कार नहीं है, वे भी बाइक के जरिए रैपिडो पर कैप्टन बनकर आसानी से काम शुरू कर सकते हैं। ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने समय के अनुसार राइड या डिलीवरी स्वीकार कर सकते हैं। यही वजह है कि यह काम छात्रों, पार्ट-टाइम काम करने वालों और यहां तक कि फुल-टाइम जॉब करने वालों के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है।

मेहनत के अनुसार आय

कमाई की बात करें तो एक गिग वर्कर शहर, समय और मेहनत के आधार पर रोज़ाना 500 से 1200 रुपये तक कमा सकता है। पीक टाइम (सुबह ऑफिस टाइम, शाम) में यह कमाई और बढ़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति फुल-टाइम काम करता है तो वह महीने में 15,000 से 30,000 रुपये तक कमा सकता है, जबकि पार्ट-टाइम में भी 8,000 से 15,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय संभव है। हालांकि, इसमें पेट्रोल खर्च और मेंटेनेंस को ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन सही प्लानिंग से अच्छी बचत भी की जा सकती है।

अपने बॉस खुद

गिग वर्क को लोग इतना पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें समय की आजादी होती है। आप जब चाहें काम करें, जब चाहें ब्रेक लें। कोई बॉस नहीं, कोई तय ऑफिस टाइम नहीं। यह खासकर उन युवाओं के लिए फायदेमंद है जो पढ़ाई के साथ कमाना चाहते हैं या अपनी नौकरी के साथ अतिरिक्त आय बनाना चाहते हैं। इसके अलावा, महिलाओं की भागीदारी भी इस क्षेत्र में धीरे-धीरे बढ़ रही है, जो इसे और समावेशी बना रहा है।

समाज के हर वर्ग की पसंद

गिग वर्क को समाज के हर वर्ग के लोग अपना रहे हैं। जहां एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह जीविका का साधन बन रहा है, वहीं मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोग इसे अतिरिक्त आय के रूप में अपना रहे हैं। कई युवा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपनी इच्छाओं और जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए भी इस विकल्प को चुन रहे हैं।

सफर का बदलता तरीका

आज के समय में लोगों की जीवनशैली भी गिग इकोनॉमी के अनुसार बदल रही है। शहरों में बड़ी संख्या में लोग अब रोजमर्रा के आवागमन के लिए बाइक टैक्सी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म तेज, सस्ते और सुविधाजनक सफर का विकल्प बन चुके हैं। ट्रैफिक जाम से बचने और कम खर्च में यात्रा करने के कारण लोग अब पारंपरिक परिवहन के बजाय इन सेवाओं को प्राथमिकता देने लगे हैं। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिल रही है, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है।

काम के साथ सुरक्षा व सेहत का संतुलन

हालांकि, गिग वर्क के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इसमें आय की स्थिरता नहीं होती, सामाजिक सुरक्षा और बीमा की कमी होती है, और कभी-कभी लंबे समय तक काम करने का दबाव भी रहता है। ऐसे में जरूरी है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय योजना पर विशेष ध्यान दें। कमाई का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाना, बीमा करवाना और समय का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है।

गिग वर्क आज के भारत में रोजगार का एक सशक्त माध्यम बन चुका है, जिसने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। यह न केवल कमाई का साधन है, बल्कि एक नई सोच और जीवनशैली का प्रतीक भी है, जहां व्यक्ति अपनी शर्तों पर काम कर सकता है। यदि इसे समझदारी और संतुलन के साथ अपनाया जाए, तो यह भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में एक स्थायी और मजबूत विकल्प साबित हो सकता है।

ऊर्जा संरक्षण एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में एक अभिनव पहल

देवेश प्रताप सिंह राठौर

झांसी। बुंदेलखंड विश्वविध्यालय ने ऊर्जा संरक्षण एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए सामूहिक कार्य प्रणाली को अपनाया है। प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा बचत और विद्युत संरक्षण के आह्वान के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नई कार्य संस्कृति विकसित की है, जिसके अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अलग-अलग कमरों में बैठाने के बजाय यथासंभव एक ही कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठाकर कार्य कराया जा रहा है। विश्वविद्यालय में इस समय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। परीक्षा की तैयारियों को समयबद्ध एवं सुचारु रूप से पूरा करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन ने लगभग 30 से अधिक शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था एक ही कॉन्फ्रेंस हॉल में की है। इस व्यवस्था से न केवल कार्यों की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है, बल्कि ऊर्जा की भी बड़ी मात्रा में बचत हो रही है। परिसर में ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग के काम के लिए भी कार्यरत समिति के द्वारा कार्य किया जा रहा है । कुलपति, कुल सचिव, वित्त अधिकारी, बी एड के राज्य समन्वयक, राज्य सह समन्वयक, विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त समन्वयक कर कर रहे हैं। अलग-अलग कमरों में एयर कंडीशनर, बिजली एवं अन्य संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता कम होने से विश्वविद्यालय परिसर में विद्युत खपत में कमी आई है। एक ही स्थान पर सभी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी के कारण परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर तत्काल चर्चा कर उनका समाधान भी तुरंत किया जा रहा है। इससे समन्वय बेहतर हुआ है और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ी है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि सामूहिक कार्य प्रणाली से टीम भावना को भी मजबूती मिलती है। अधिकारी एवं कर्मचारी एक-दूसरे के साथ निरंतर संवाद में रहते हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनती है। बीएड प्रवेश परीक्षा जैसे बड़े आयोजन में यह व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रही है।विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार यह पहल केवल ऊर्जा संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि "वर्किंग टुगेदर" की भावना को भी सशक्त कर रही है। संसाधनों के साझा उपयोग का यह मॉडल भविष्य में अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए भी प्रेरणादायक बन सकता है। शिक्षा जगत में बुंदेलखंड विश्वविध्यालय की यह पहल एक अनूठे उदाहरण के रूप में देखी जा रही है, जहां ऊर्जा बचत, बेहतर समन्वय और तेज कार्य निष्पादन को एक साथ सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बिजली, किसान समस्याओं का किया निरीक्षण

- ट्रान्स गंगा सिटी पावर हाउस से गांवों को मिलेगी बिजली, पुनर्वास राशि का निर्देश

संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने ट्रान्स गंगा सिटी पहुंचकर क्षेत्र की बिजली समस्या का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को शंकरपुर, पिपरी और सन्नी सहित कई गांवों की बिजली ट्रान्स गंगा सिटी पावर हाउस से तत्काल जोड़ने के निर्देश दिए।

विधायक ने मौके पर जेई आशीष गुप्ता के साथ फीडर का निरीक्षण किया और उच्चाधिकारियों से वार्ता कर ग्रामीणों को शीघ्र राहत दिलाने को कहा।विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि उनकी निधि से बिजली विभाग को पांच करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी गली, मोहल्ले या घर में बिजली की समस्या न रहे। उन्होंने जनता से अपील की कि यदि कहीं भी समस्या आती है तो वे सीधे उन्हें अवगत कराएं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से बिजली संकट से जूझ रहे थे। अब तक ऐरा भदियार फीडर से बिजली आपूर्ति की जा रही थी, जिससे लंबी दूरी के कारण बार-बार फॉल्ट, रोस्टिंग और लो वोल्टेज जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। भीषण गर्मी में ग्रामीणों को इन समस्याओं के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक स्वयं ट्रान्स गंगा सिटी पहुंचे और समाधान के निर्देश दिए।इसी दौरान विधायक ने यूपीसीडा के साइड ऑफिस पहुंचकर किसानों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन किसानों को पुनर्वास के तहत 50 हजार रुपये की सहायता राशि नहीं मिली है और जिन्हें विकसित प्लॉट निशुल्क मिलने हैं, उन्हें जल्द से जल्द कैंप लगाकर वितरित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सन्नी सुभाष लोधी, प्रधान शंकरपुर सर्वेश लोधी, बनी प्रधान रतिभान, लगड़ापुर प्रधान अखिलेश, किसान नेता ब्रजेश सिंह, हीरेन्द्र निगम, रानू मिश्र, गोलू त्रिवेदी और पिंकू तिवारी सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

एयरपोर्ट पर 2.58 करोड़ के सोने के साथ यात्री गिरफ्तार

संवाददाता

अमृतसर। श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक यात्री से 2.58 करोड़ रुपये कीमत का सोना बरामद किया है। यह यात्री मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच-119 से अमृतसर से कुआलालंपुर जा रहा था।

कस्टम अधिकारियों को यात्री की गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद उसे रोका गया। अधिकारियों ने उसकी गहन जांच की, जिसमें यात्री के पास से 1,676 ग्राम 24 कैरेट सोना बरामद किया गया। यह सोना कड़ा और गोल्ड बिस्किट के रूप में छिपाकर रखा गया था। बरामद सोने की कुल कीमत करीब 2.58 करोड़ रुपये बताई जा रही है। कस्टम विभाग ने सोने को कस्टम एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया है। यात्री को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का मानना है कि इस मामले के तार किसी बड़े सोना तस्करी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जांच की जा रही है।

भीषण गर्मी को लेकर डीएम सख्त

बिजली-पानी व्यवस्था पर 24×7 निगरानी

मुन्नालाल, जेल चौराहा और नंदनपुरा पावर हाउस के हेल्प डेस्क नंबर जारी, शिकायत पर तत्काल होगी कार्रवाई

संवाददाता

झांसी, उत्तर प्रदेश। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जनपद में निर्बाध विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता को बिजली और पानी की समस्या से जूझना न पड़े, इसके लिए सभी विभाग संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और आगे भी इसके बढ़ने की संभावना है। ऐसे में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से पेयजल संकट गहरा सकता है। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि आज से ही "पेनफुल प्वाइंट" का सर्वे शुरू किया जाए, ताकि समय रहते आवश्यक सुधार कार्य कराए जा सकें।24 घंटे संचालित होंगे हेल्प डेस्क नंबरजनता की सुविधा के लिए तीन प्रमुख पावर हाउसों के हेल्प डेस्क नंबर सार्वजनिक किए गए हैं, जो 24×7 संचालित रहेंगे—मुन्नालाल पावर हाउस – 9532595694जेल चौराहा फीडर – 9415132090नंदनपुरा पावर हाउस – 8765978473जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी कि यदि इन नंबरों पर शिकायतों का जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।कैंट क्षेत्र में अलग फीडर बनाने पर जोरबैठक में रक्षा विभाग के अधिकारियों ने कैंट क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या उठाई। इस पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को संयुक्त सर्वे कर अलग फीडर की व्यवस्था जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जेल चौराहे स्थित 33 केवी फीडर के उच्चीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके पूरा होने पर कैंट क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली आपूर्ति हो सकेगी।पेयजल संकट रोकने के निर्देशजिलाधिकारी ने जल संस्थान और विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि दतिया गेट फीडर सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित न होने पाए। उन्होंने सुझाव दिया कि जहां सुबह वोल्टेज बेहतर मिलता है, वहां जलापूर्ति का समय बढ़ाया जा सकता है।बरुआसागर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर तक पानी पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में टुल्लू पंप लगाकर अवैध रूप से पानी खींचने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे आगे के घरों में पानी नहीं पहुंचता। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ धारा 152 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।ट्रांसफार्मर और सिंचाई समस्याओं पर भी निर्देशजिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर, अघोषित बिजली कटौती और ट्यूबवेल बंद होने जैसी समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।बैठक में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हिमांशु गौतम, अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा, मुख्य अभियंता के.पी. खान, अधीक्षण अभियंता पुष्कर सिंह सहित विद्युत विभाग और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे।

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर

संवाददाता

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग के आह्वान पर अमल करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान मेट्रो ट्रेन से सफर कर मितव्ययता का उदाहरण प्रस्तुत किया।

उल्लेखनीय है कि देश में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, प्रदूषण और वर्तमान वैश्विक संकट के दृष्टिगत भविष्य के लिए ईंधन की बचत और वर्तमान में की जा रही खपत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो के अधिक उपयोग की अपील की है। इसी दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो में यात्रा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आम यात्रियों के बीच रहकर सफर किया और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मेट्रो सफर की सभी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र में काफी चर्चा रही। इसे एक प्रतीकात्मक और प्रभावशाली संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि यदि जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं, तो सभी इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मेट्रो सफर के संदर्भ में कहा कि मेट्रो जैसे आधुनिक परिवहन साधन समय की बचत के साथ पर्यावरण-संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बड़े शहरों में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बेहद आवश्यक है। इससे न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी कहा कि भारत तेजी से आधुनिक और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां परिवहन व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिल्ली मेट्रो की व्यवस्था, समयबद्धता और यात्री सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि देश के अन्य शहरों में भी इस तरह की व्यवस्थाओं का विस्तार होना चाहिए। मध्यप्रदेश में भोपाल और इंदौर के पश्चात अन्य बड़े नगरों में मेट्रो ट्रेन सुविधा का विस्तार इसी सुविचारित योजना का हिस्सा है। हमारा देश स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन मोबिलिटी और स्मार्ट सिटी मिशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

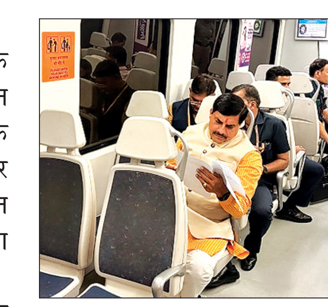

रामेश्वरम मंदिर में लड्डू घोटाला मामला: 6 कर्मचारी निलंबित

संवाददाता

रामनाथपुरम। अरुलमिगु रामनाथस्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं को मुफ्त वितरित किए जाने वाले लड्डू प्रसाद को अवैध रूप से बेचकर 3 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में मंदिर प्रशासन ने एक जूनियर असिस्टेंट सहित छह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।

मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पिछले मार्च महीने में मंदिर के संयुक्त आयुक्त सेलत्तुरई ने लड्डू प्रसाद की तैयारी और आय-व्यय खातों की अचानक जांच कराई। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। प्राथमिक जांच में पता चला कि प्रसाद निर्माण और बिक्री के प्रभारी जूनियर असिस्टेंट के. पंचमूर्ति ने मुफ्त बांटे जाने वाले लड्डुओं की संख्या रिकॉर्ड में कम दिखाकर उन्हें स्टॉलों के माध्यम से अवैध रूप से बेच दिया। इसके जरिए बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया गया। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों और अन्य स्टाफ से लगातार पूछताछ की गई।

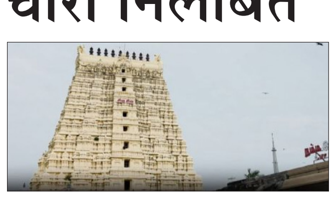

21 करोड़ की अफीम के साथ 5 गिरफ्तार

संवाददाता

गुवाहाटी। असम में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कामरूप पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अमीनगांव में एक बस से करीब 21 करोड़ 36 लाख मूल्य की हेरोइन और अफीम बरामद की है। इस मामले में पांच कथित तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

असम पुलिस के सीपीआरओ ने गुरवार को बताया कि, गुप्त सूचना मिली थी कि मणिपुर के क्वाक्टा से पड़ोसी राज्य की ओर जा रही बस संख्या एएस 06 एसी 7555 के जरिए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है।

सूचना में यह भी बताया गया था कि बस में कोई सामान्य यात्री नहीं है और उसमें केवल तस्कर सवार हैं। सूचना के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अमीनगांव में बस को रोककर तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान बस में बने गुप्त खाने से 197 साबुन के डिब्बों में छिपाकर रखी गई 2.561 किलो हेरोइन और 8 किलो अफीम बरामद की गई।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारी करेंगे सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम

संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में दो दिनों वर्क फ्रॉम होम और सरकारी वाहनों के ईंधन की खपत 20 फीसदी कम करने जैसी कई घोषणाएं कीं। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद लिया गया है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस कांफ्रेंस करते बताया कि वैश्विक अनिश्चितता के समय हर नागरिक अपनी जीवनशैली में छोटे बदलाव करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे।

एसएसबी-पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चीन-कतर और सऊदी की करेंसी के साथ एक गिरफ्तार

संवाददाता

किशनगंज। बिहार में भारत-नेपाल सीमा के किशनगंज जिला अन्तर्गत गलगलिया थाना क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, भारतीय एवं चीन-कतर और सऊदी की करेंसी बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी चांद मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों के कारोबार से जोड़कर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर गलगलिया थाना क्षेत्र के नेंगडाडुबा गांव निवासी 48 वर्षीय चान मोहम्मद के घर पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई एसएसबी भातगांव, एसएसबी नेमुगुड़ी तथा स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। छापेमारी के दौरान घर से 120 ग्राम ब्राउन शुगर, एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के घर से 7 लाख 76 हजार 500 रुपये भारतीय मुद्रा तथा 1 लाख 28 हजार रुपये नेपाली मुद्रा जब्त की। इसके अलावे चीन, कतर और साउदी अरब की विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है। इनमें कतर के 27 नोट, मलेशिया का एक नोट, चीन के 10 नोट और सऊदी अरब के 12 नोट शामिल हैं। बरामद विदेशी मुद्रा को लेकर भी जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। गुरुवार को गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि बरामद ब्राउन शुगर की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपये आंकी गई है। छापेमारी के बाद आरोपी चान मोहम्मद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस संयुक्त अभियान में ठाकुरगंज अंचल निरीक्षक पंकज पंथ, गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक भूषण झा, महिला सिपाही सपना कुमारी, मनीषा कुमारी, बीएचजी तरुण कुमार, राजेंद्र गणेश और मिथुन गणेश सहित एसएसबी नेमुगुड़ी व भातगांव की टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मालिक, प्रकाशक व मुद्रक- सुनील कुमार तिवारी द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट नं. ०४, ग्राउंड फ्लोर, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नियर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं ०२, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-४०००६३ से मुद्रित व ६१७, बिल्डिंग नं. १४ नियर शिव शक्ति बिल्डिंग, गोलीबार रोड, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुंबई-४०००५५ से प्रकाशित। **संपादक सुनील कुमार तिवारी,** RNI. NO. MAHMUL/2017/74054, **संपादकीय कार्यालयः कंटेश्वर सिंह चाल, अपोजीट एकताड़ मंडल, साईं बाबा रोड, खार (पूर्व), मुंबई- 400051, Mob. 8898271111**